कम्प्यूटर उद्योग का विकास

616. श्री अजीत जोगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कम्प्यूटर उद्योग का कितना विकास हुआ ;

(ख) सरकार कम्प्यूटर उद्योग को बढ़ावा देने और इस अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है ;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में इनफारमेशन टैक्नोलॉजी एक्सपर्ट फेडरेशन से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडवर्डो फलेरो) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटर उद्योग का वार्षिक विकास नीचे दिए अनुसार है :—

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रुपये में)	विकास दर (%)
1992	970	16.87
1993	1050	8.25
1994	1300	23.8
	(अनुमानित)	

(ख) भारतीय कम्प्यूटर उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित वित्तीय एवं कर संबंधी तथा वास्तविक नीतियां लागू हैं :—

(i) विनिर्माण के लिए वस्तु लाइसेंस मुक्त हैं ।

(ii) कम्प्यूटर उद्योग की स्थापना करने के लिए स्थापना-स्थल संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है ।

(iii) आयात-निर्यात नीति का उदारीकरण, जिससे यथातिल पूंजीगत वस्तुओं की निर्बाध रूप से प्राप्ति संभव हो ।

(iv) इकाइयों को अपनी क्षमता का विस्तार करने तथा एक ही लाइसेंस के अंतर्गत कई वस्तुओं का उत्पादन करने की अनुमति दी जाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम लागत पर अधिक उत्पादन किया जा सके तथा प्रतिष्ठापित पूंजीगत उपस्करों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सके ।

(v) इलेक्ट्रानिकी विभाग का मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण (एसटीक्यूसी), निदेशालय, आईएसओ 9000 अर्हता प्राप्त करने में विनिर्माताओं का मार्गदर्शन करता है ।

(vi) 51% तक विदेशी साम्यपूंजी वाले विदेशी सहयोग के प्रस्ताव स्वतः अनुमति प्राप्त हैं ।

(vii) आयात-निर्यात नीति 1992–97 के अनुसार कम्प्यूटर के विनिर्माण के लिए संघटक-पुर्जों का मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति दी जाती है ।

(viii) स्वदेशी उद्योग को आवश्यक संरक्षण प्रदान करने के लिए 1.5 लाख रुपए तक लागत बीमा भाड़ा मूल्य की कम्प्यूटर प्रणालियों आयात की निषेधात्मक सूची में है तथा उनके लिए आयात लाइसेंस लेना अपेक्षित है ।

(ix) कम्प्यूटरों के निर्यात के लिए उपादानों का आयात करने के लिए मूल्य संवर्धन संबंधी मानदण्ड यात्रा/मूल्य पर आधारित अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं तथा निर्यातकर्ता शुल्क-मुक्त उपादान प्राप्त कर सकते हैं।

(x) ईएचटीपी योजना के अंतर्गत कम्प्यूटर प्रणालियों के संयोजन को प्रोत्साहित किया जाता है तथा नाममात्र के मूल्य संवर्धन पर उनका निर्यात किया जा सकता है।

(xi) कम्प्यूटर प्रणालियों के निर्यात से निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 30% की दर से विशेष अग्रदाय लाइसेंस (एसआईएल) प्राप्त होता है। एसआईएल का मुक्त रूप से हस्तांतरण किया जा सकता है तथा इससे बाजार में प्रीमियम प्राप्त होता है। इससे निर्यात के मूल्य को प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता मिलती है।

(xii) कम्प्यूटर प्रणालियों के विनिर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक तथा गैर-इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों पर लगाया जाने वाला आयात शुल्क सीमा शुल्क की रियायती दर पर है ताकि विनिर्माण की लागत को कम रखा जा सके।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात संघ नामक किसी भी संगठन ने इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, भारत सरकार के समक्ष सुझाव प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

Indo-Japanese Software tie-ups

617. MISS SAROJ KHAPARDE: will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a large scope for Indo-Japanese Software tie-ups; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) During 1993-94. the Software exports to Japanese market is about 4 per cent of the total Software export from India. Japanese. companies have been exploring the possibility of sourcing software from India by setting up Joint Ventures, business tie-ups, setting up their own, wholly owned subsideries, etc.

During February/March, 1995, a Japanese Information Technology (IT) delegation comprising experts from Industry visited India under a visit sponsored by Electronics and Computer Software Export Promotion Council (ESC) in association with the Japan External Trade Organisation (JETRO) under their Asia Cooperation programme. During the visit of this delegation, seminars were organised on "The Present and Future Trends of the Japanese Information Technology Industry" to disseminate information about the opportunities in the area of computer software in Japan.

Purchase of substandard drugs in Government hospitals

6IS. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whehcr large scale irregularities in ihe purchase of drugs and other items and also mismanagement are prevalent in Government hospitals in the country, including Arunachal Pradesh; and